सिंचाई परियोजनाओं को कार्यान्वित करने में विलम्ब होना

3001. श्री आस मोहम्मद: क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केंद्रीय सरकार को सिंचाई परियोजनाओं को कार्यान्वित करते समय विभिन्न विभागों के बीच विवाद होने की जानकारी मिली है जिसके फलस्वरूप इन परियोजनाओं का उचित ढंग से कार्यान्वयन नहीं हो पाया है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे विवादों को निपटाने के लिए क्या प्रयास किए गए है ; और

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई मार्ग-निर्देश जारी किया है ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वी० रंगैया नायडू) : (क) विभिन्न सरकारी विभागों के बीच विवादों जिनसे सिंचाई परियोजनाओं के क्रियान्वयन, में विलम्ब होता है, के बारे में रिपोर्ट केन्द्र में प्राप्त नही हुई है । परियोजनाओं के क्रियान्वयन में विलम्ब के प्रमुख कारणों में एक कारण निजी एवं वन भूमि के अधिग्रहण में आने वाली कठिनाइयां हैं ।

(ख) और (ग) सिंचाई परियोजनाओं के मूल्यांकन के दिशा निर्देशों के अनुसार, पर्यावरणीय और/अथवा वन दृष्टियों से स्वीकृत किसी सिंचाई परियोजना को निवेश स्वीकृति के लिए एक पूर्व आवश्यकता है। विभिन्न विभागों के बीच उचित समन्वय सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों को यह सलाह भी दी गयी है कि वे तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन के लिए केन्द्रीय जल आयोग को प्रस्तुत करने के पूर्व, परियोजना के विभिन्न पहलुओं पर विचार करने के लिए राज्य स्तरीय बहु विषयक यूनिट की स्थापना करें । उन परियोजनाओं जिनमें अंतर्राज्यीय नदी के जल की हिस्सेदारी और अन्य राज्यों में जलमग्न होने वाले क्षेत्र जैसे अन्तर्राज्यीय मुद्दे शामिल हैं, के बारे में राज्य सरकार को उनकी निवेश स्वीकृति से पूर्व, संबंधित राज्य सरकारों की सहमति प्राप्त करना भी अपेक्षित है।

मध्य प्रदेश में सिंचाई परियोजनाये

3002. श्री राघवजी : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित कितनी सिंचाई परियोजनाओं को 1992 से उनके संबंध में और स्पष्टीकरण लेने के लिए वापस भेजा जा चुका है ; और

(ख) प्रत्येक परियोजना वापस किए जाने के क्या कारण हैं ?

जल संसाधन मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री पी.वी.रंगैया नायडू) : (क) और (ख) 1-1-1992 के बाद से राज्य सरकार को लौटाये गये मध्य प्रदेश के पांच वृहद सिंचाई परियोजना प्रस्तावों में से लोअर गोई और बीना काम्पलैक्स फेज-I परियोजनाओं की आयोजना में मूल कमियां पाई गई थी । शेष तीन परियोजनाओं नामशः परवती, गोपद मयार और कुनु को आठवीं योजना में शामिल नहीं किया गया है ।

On-going of prigation Project in the country

3003. SHRI T. VENKATRAM REDDY: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) the number of on-going major and medium irrigation projects in the country;

(b) the present stage of these projects;

(c) the original and latest estimated cost of the projects;

(d) the amount spent on these projects during the last three years;

(e) the amount proposed to be spent on these projects during the remaining period of the Eighth Five Year Plan; and

(f) the names of the projects which are likely to be completed over the ninth Five Year Plan?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P. V. RANGAYYA NAIDU): (a) 158 major, 226 medium & 95 extension/renovation/modernisation (ERM) irrigation schemes are on-going in VIII Plan.

(b) Against latest estimated cost of Rs. 70,966.34 crores, the anticipated expenditure till March, 1995 is Rs 34,157.28 crores.

(c) Out of above on-going projects, 103 major, 171 medium and 21 ERM projects have been given investment clearance by the Planning Commission. Their approved estimated cost and latest estimated cost are Rs. 11,593.77 crores and Rs. 48,296.85 crores respectively.

(d) The anticipated expenditure during the period 1992-95 is Rs. 9,536.35 crores.

(e) Annual Plans 1995-96 and 1996-97 have not been finalised.

(f) The completion of the projects in VIII Plan depends upon allocation of funds during the remaining two years (1995-97) of VIII Plan.

Construction of barrage on river Vansadhara at Neradi

3004 SHRI BHAGABAN MAJHI: Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state:

(a) whether Government have a proposal for the construction of a barrage at Neradi on the river Vansadhara;

(b) whether the Governments of Andhra Pradesh and Orissa have signed a agreement for the same;

(c) if so, the details of the agreement;

(d) the total areas in Orissa and Andhra Pradesh likely to be submerged on the construction of the barrage;

(e) the number of tribal villages, the details of forests etc. which are going to be submerged; and

(f) the steps taken/proposed to provide rehabilitation to the affected people?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P. V. RANGAYYA NAIDU): (a) Yes Sir. Neradi Barrage is a competent of Vansadhara Project State-II.

(b) and (c) An agreement was reached between the Chief Ministers of Andhra Pradesh and Orissa in July, 1961 for construction of a barrage at Neradi across river Vansadhara involving acquisition of 106 acres of land in Orissa territory by Government of Andhra Pradesh. Subsequently, in September; 1962; it was agreed between Government of Andhra Pradesh and Orissa that water available in the Vansadhara basin are to be shared on 50:50 basis. Subsequently in an interestate meeting convened by the Union Minister of Water Resources with the Chief Minister of Andhra Pradesh and Orissa in January, 1987, it was agreed to reformulate Vansadhahara Project Stage-II in accordance with the provisions of 1961 agreement. Discussions between the Chief Ministers of Andhra Pradesh and Orissa also took place in June, 1992 and recently in December, 1994 wherein it was agreed that the land to be acquired in Orissa territory shall not be more than 100 acres.

(d) The submergence due to construction of Neradi barrage is within the river margins and flood embankments. Acquisition of land in Orissa territory is limited to 106 acres.